

राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक:- एफ.20 (I-10)/आई.डब्ल्यू.एम.पी./निजमूस/2011-12/2164-2205 दिनांक: 26/2/13

परिपत्र

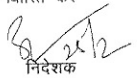
आई.डब्ल्यू.एम.पी. योजना अन्तर्गत प्रतिवर्ष भारत सरकार द्वारा राज्य को नवीन जलग्रहण परियोजनाओं हेतु क्षेत्रफल आवंटित किया जाता है तथा तदुपश्चात जिलों द्वारा भारत सरकार द्वारा निर्धारित 13 विन्दुओं के आधार पर ब्लॉकवार तैयार की गई प्राथमिकता सूची के आधार पर प्राथमिक परियोजना प्रतिवेदन (पी.पी.आर.) तैयार कर प्रेषित की जाती है।

पूर्व में जिलों द्वारा आवंटित क्षेत्रफल के विरुद्ध पंचायत समितिवार स्वयं प्राथमिकता तय कर पी.पी.आर. प्रेषित की जाती थी। आगामी वर्षों में किसी एक ब्लॉक में अधिक तथा दूसरे ब्लॉक में कम परियोजनाएँ स्वीकृत ना हो अपितु सभी ब्लॉक में समान रूप से परियोजनाएँ स्वीकृत हो पाएँ इस हेतु जिलों को निम्नानुसार विन्दुओं के आधार पर पंचायत समिति की प्राथमिकता तय कर पी.पी.आर. भिजवाने हेतु निर्देशित किया जाता है :

1. सर्वप्रथम समस्त पंचायत समिति को भारत सरकार द्वारा जलग्रहण परियोजनाओं की प्राथमिकता तय करने हेतु निर्धारित 13 विन्दुओं में से प्रथम विन्दु (बीपीएल प्रतिशत) के क्रम में अधिक से कम रखते हुए पंचायत समिति की वरीयता सूची तैयार करें।
2. जिन पंचायत समितियों में पूर्व में कोई भी आई.डब्ल्यू.एम.पी. परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है, उनमें परियोजना आवश्यक रूप से ली जायें।
3. इस प्रकार जिले की समस्त पंचायत समितियों में परियोजनाएँ ली जायें कि सभी पंचायत समितियों में समान क्षेत्रफल/परियोजनाएँ हों जायें।
4. पंचायत समितियों में समान परियोजना होने की स्थिति में भारत सरकार द्वारा निर्धारित 13 विन्दुओं में से प्रथम विन्दु (बीपीएल प्रतिशत) के अनुरूप जिस पंचायत समिति में बी.पी.एल. का प्रतिशत अधिक है उस पंचायत समिति में परियोजना लिये जाने को प्राथमिकता दी जावे।

अतः भविष्य में जिलों द्वारा पंचायत समिति की प्राथमिकता उपरोक्तानुसार निर्धारित कर आवंटित किये गये क्षेत्रफल अनुसार ही पी.पी.आर. प्रेषित की जायें।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

  
निदेशक

प्रतिलिपि:-

क्रमांक:- एफ.20 (I-10)/आई.डब्ल्यू.एम.पी./निजमूस/2011-12/2164-2205 दिनांक: 26/2/13

1. अतिरिक्त निदेशक (आई.डब्ल्यू.एम.पी./प्रशासन), निदेशालय, जयपुर।
2. समस्त उप निदेशक /P.O.(L.R), निदेशालय, जयपुर।
3. समस्त परियोजना प्रबन्धक (WCDC) एवं अधिशाही अभियन्ता (भू संसाधन) जिला परिषद.....
4. ए.सी.पी., निदेशालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेब साईट पर अपलोड करावे।

  
निदेशक